(43)

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-ए0/वी0-कोर्ट मैनेजर-10/2010/....917.....जे0, पटना, दिनांक..28/03/11

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:- वित्त विभाग ।

विषय:- 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में उच्च न्यायालय, पटना के लिये कोर्ट्स मैनेजर के दो पद तथा तीस न्यायमंडलों के लिए कोर्ट्स मैनेजर के तीस पद पाँच वर्षों के लिये संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु कुल 32(बत्तीस) पदों का सृजन की स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्यों में न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिये भारत सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के उच्च न्यायालय में दो कोर्ट्स मैनेजर एवं प्रत्येक न्यायमंडल में एक कोर्ट्स मैनेजर के पद सृजन की आवश्यकता बतायी गई है जिसके आलोक में राज्य में कुल 32 कोर्ट्स मैनेजर का पद सृजित किया जाता है।

2. भारत सरकार द्वारा कोर्ट्स मैनेजर की नियुक्ति हेतु अर्हत्ता एम0बी0ए0 निर्धारित की गई है परन्तु राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्र सं0-9894-95 दिनांक 24.07.10 एवं 15323 दिनांक 04.08.10 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार न्यायमंडलों तथा उच्च न्यायालय, पटना के लिए कोर्ट्स मैनेजर के निमित्त निम्नांकित योग्यता/अर्हत्ता एवं वेतन का निर्धारण किया गया है:-

(क) उच्च न्यायालय, पटना के लिये कोर्ट्स मैनेजर :-

(i) योग्यता - एम0बी0ए0 या समकक्ष (सूचना एवं प्रावैधिकी में) ।
(ii) उम्र सीमा - 30 से 35 वर्ष ।
(iii) अनुभव - प्रबंधकीय कार्य के अनुभव प्राप्त को प्राथमिकता ।
(iv) वेतन - 65,000/-(पैसठ हजार) प्रतिमाह नियत वेतन ।
(v) नियुक्ति की शर्त्त - संविदा के आधार पर पाँच वर्षो के लिये ।

(ख) राज्य के 30(तीस) न्यायमंडलों के लिये कोर्ट्स मैनेजर - 30(तीस) पद ।

(i) योग्यता - एम0बी0ए0 (लॉ डिग्री सहित योग्यताधारी को प्राथमिकता) ।
(ii) उम्र सीमा - 30 से 35 वर्ष ।
(iii) अनुभव - प्रबंधकीय कार्य के अनुभव प्राप्त को प्राथमिकता ।
(iv) वेतन - 65,000/-(पैसठ हजार) प्रतिमाह नियत वेतन ।
(v) नियुक्ति की शर्त्त - संविदा के आधार पर पाँच वर्षो के लिये ।

3. उक्त से संबंधित प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय विवरणी संलग्न है।

4. (क) उच्च न्यायालय, पटना के लिये कोर्ट्स मैनेजर के वेतनादि संबंधी व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-102 उच्च न्यायालय, उपशीर्ष-0001 उच्च न्यायालय, पटना(प्रभृत) के वेतन एवं जीवन यापन भत्ते के विषय शीर्ष के अंतर्गत होगा।

तक के न्यायिक पदाधिकारियों यथा :- कुल ... प्रत्येक न्यायमंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ... राज्य के प्रत्येक न्यायालय ... 618 पदों पर आवेश ...

(ख) तीस न्यायमंडलों के लिये कोर्ट्स मैनेजर के वेतनादि संबंधी व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105 सिविल और सेशन्स न्यायालय, उपशीर्ष-0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अंतर्गत वेतन एवं जीवन यापन भत्ते के विषय शीर्ष के अंतर्गत होगा।

5. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0-अनुमानित व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-राजेन्द्र कुमार मिश्र
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-217/जे0, पटना, दिनांक:-28/03/11

प्रतिलिपि:-अनुमानित व्यय विवरणी सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथाकथित।

ह0/-राजेन्द्र कुमार मिश्र
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-217/जे0, पटना, दिनांक:-28/03/11

प्रतिलिपि:- अनुमानित व्यय विवरणी सहित महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथाकथित।

28/3/11
(राजेन्द्र कुमार मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

O/C
As
28/3/11

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या बी/स्था(ब्रा-सं)-6 26/2010 446 /जे0, पटना, दिनांक:- 15/7/11

सेवा में

महानिबंधक, बिहार
औरंगजेब पथ, पटना ।

आदेशानुसार एवं
मैं यथादेशित

द्वारा:- विशेष विभाग ।

विषय:- राज्य के प्रत्येक न्यायमंडल में चरणबद्ध तरीके से अपने प्रथम चरण में प्रत्येक न्यायमंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर से सब जज-1 स्तर तक के न्यायिक पदाधिकारियों यथा:- कुल 618 के लिए 618 ''डिपोजिशन राईटर सह-टंकक'' के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक न्यायमंडल में चरणबद्ध तरीके से प्रथम चरण में प्रत्येक न्यायमंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर से सब जज-1 स्तर तक के न्यायिक पदाधिकारियों यथा :- कुल 618 के लिए 618 ''डिपोजिशन राईटर-सह-टंकक'' के कुल 618 पदों पर आदेश निर्गत की तिथि से कुल अनुमानित स्थापना खर्च 10,80,43,704/-(दस करोड़ अस्सी लाख तैंतालीस हजार सात सौ चार) रुपये में इन पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है (व्यय विवरणी संलग्न)।

2. ''डिपोजिशन राईटर-सह-टंकक'' के 618 पद आदेश निर्गत होने की तिथि से वेतनमान 5200-20200/- ग्रेड पे-2400 में सृजन का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-उप शीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय अंतर्गत वेतन/भत्ते विषय शीर्ष से होगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे तथा संबंधित सभी जिला कोषागारों से राशि की निकासी होगी ।

4. उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में दिनांक-12.07.2011 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सं0-19 में स्वीकृति प्राप्त है।

अनु0- (क) व्यय विवरणी।
(ख) जाँच पत्र
(ग) वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति संबंधी टिप्पणी पृष्ठ की छाया प्रति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:- 446 /जे0, पटना, दिनांक:- 15/7/11

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:- 446 /जे0, पटना, दिनांक:- 15/7/11

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा)/विधि विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:- 446 /जे0, पटना, दिनांक:- 15/7/11

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-12.07.2011 के मद संख्या-19 के प्रसंग में तथा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:- 446 /जे0, पटना, दिनांक:- 15/7/11

प्रतिलिपि:- सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7/11
(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

राज्य के सभी न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लेकर सब जज-1 के स्तर तक न्यायिक पदाधिकारियों के लिए "डिपोजिशन राईटर" के पद

सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी:

रुपये में

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	पे बैण्ड/ग्रेड पे	प्रारंभिक वेतन	महंगाई भत्ता @ 35%	मकान किराया भत्ता @ 10%	चिकित्सा भत्ता	योग	प्रस्तावित पदों के लिए प्रतिवर्ष कुल व्यय भार
1.	डिपोजिशन राइटर	618	5200-20200/-2400/-	9910	3468	991	200	14569	14569×618×12 = 108043704.00
									कुल:- 108043704.00

(दस करोड़ अस्सी लाख तैंतालीस हजार सात सौ चार) रुपये

नोट:- 1. मकान किराया भत्ता की गणना श्रेणी 'सी' के शहरों के लिए अनुमान्यता के आधार पर की गई है। अन्य शहर तथा पटना के लिए अनुमान्यता के अनुसार गणना परिवर्तनीय होगा।

2. पटना के लिए परिवहन भत्ता भी अनुमान्य होगा।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

46

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-बी0/स्था(उ0न्या0) 06-23/2010...../जे0, पटना, दिनांक .....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
बीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पचारिक रूप परामर्शित द्वारा: * वित्त विभाग ।

विषय:- राज्य के सभी न्यायमण्डलों के सभी अवर न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आशुलिपिक के कुल 536 तथा लिपिक के कुल 1028 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य के न्यायिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के मामले में राज्य के सभी न्यायमण्डलों में वर्त्तमान में आशुलिपिक एवं लिपिक के लिए स्वीकृत पदों में वृद्धि किए जाने से संबंधित उच्च न्यायालय पटना के पत्र सं0-7532/प्रशासन(विविध) दिनांक 25.06.2012 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने आशुलिपिक के कुल 536 एवं लिपिक के कुल 1028 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की है जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :-

क्र0	पद का नाम	अतिरिक्त पदों की संख्या	पे-वैण्ड
1.	आशुलिपिक	536	पी0बी0-1/2400
2.	लिपिक	1028	पी0बी0-1/1900

3. उक्त सृजित पदों का वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुमानित स्थापना व्यय 28,21,85,184/-(अट्ठाईस करोड़ इक्कीस लाख पच्चासी हजार एक सौ चौरासी) रूपये भारित होगा। एतद्संबंधी अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी संलग्न है।

4. उक्त स्थापना व्यय की राशि का विकलन बजट शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन लघुशीर्ष-105 सिविल और सेशन्स न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय अंतर्गत वेतन/भत्ते विषय शीर्ष में होगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार होंगे तथा इसकी निकासी सभी जिला कोषागारों से होगी।

5. उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में दिनांक 17.08.2012 को मंत्रिपरिषद् की हुई बैठक के मद सं0-11 में स्वीकृति प्राप्त है।

अनु0- (क) अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी।
(ख) जॉच पत्र।
(ग) वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति संबंधी टिप्पणी/पृष्ठ की छायाप्रति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

(क0प्र0330)

ज्ञाप सं0 ...../जे0, पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:-अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी सहित राज्य के सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 यथाकथित।

ह0/ विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0 ...../जे0, पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:-अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी सहित महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा) तथा विधि विभाग (बजट शाखा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथाकथित।

ह0/ विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-...../जे0, पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:- अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी सहित प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 17.08.2012 के मद सं0-11 के अनुपालन के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0 यथाकथित।

ह0/ विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-410/जे0, पटना, दिनांक 22/08/12

प्रतिलिपि:- अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी सहित सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथाकथित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

न्यायमंडलों में सभी अवर न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आशुलिपिक एवं पर्याप्त संख्या में लिपिक के पद सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	पे बैंड/ग्रेड पे (रू0)	प्रारंभिक वेतन (रू0)	महंगाई भत्ता 65: (रू0)	मकान किराया भत्ता 10: (रू0)	चिकित्सा भत्ता (रू0)	योग	प्रतिवर्ष संभावित व्यय (रू0 में)
1.	आशुलिपिक	536	5200--20200/2400	9910	6442	991	200	17,543	17543X536X12 = 112836576
2.	लिपिक	1028	5200--20200/1900	7730	5025	773	200	13,728	13728X1028X12 = 169348608

कुल - 28,21,85,184

(अठाईस करोड़ इक्कीस लाख पच्चासी हजार एक सौ चौरासी)

नोट:- (1) उपर्युक्त व्यय विवरणी ''सी0'' श्रेणी के शहर के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता पर आधारित है।

(2) पटना शहर के लिए सृकिजत पदों पर पटना के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता के आधार पर अनुमानित वार्षिक व्यय परिवर्तनीय होगा।

(3) अवर्गीकृत शहरों के लिए मकान किराया भत्ता तदनुसार परिवर्त्तनीय होगा।

23/8/12

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

ज्ञाप संo वी0/स्था0(न्या0-गा0) 07 17/2014...819.../वि0, पटना, दिनांक...19-03-15

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
कौशल पटेल पथ, पटना ।

अनौपचारिक रूप से प्रस्तावित

द्वारा:- वित्त विभाग

विषय :- न्यायमंडल शेखपुरा के लिए अराजपत्रित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के आवश्यक कुल-145 (एक सौ पैंतालीस) पदों के सृजन के संबंध में।

आदेश - स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार ने न्यायमंडल शेखपुरा की स्थापना हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग-3 एवं वर्ग-4) के लिए निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है :-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	पे-बैन्ड	ग्रेड-पे
1.	डी0जे0 सिरेस्तेदार	01	PB-3	5400/-
2.	क्रिमिनल सिरेस्तेदार	01	PB-2	4200/-
3.	सबजज सिरेस्तेदार	01	PB-2	4200/-
4.	मुंसिफ सिरेस्तेदार	01	PB-2	4200/-
5.	लिपिक	61	PB-1	2400/-
6.	स्टेनोग्राफर	20	PB-1	2400/-
7.	डिपोजिशन राईटर	10	PB-1	2400/-
8.	चालक	03	PB-1	1900/-
9.	दफ्तरी	03	PB-1	1800/-
10.	प्रोसेस सर्वर	05	PB-1	1800/-
11.	पीऊन/अर्दली	37	PB-1	1800/-
12.	नाईट गार्ड (चौकीदार)	02	PB-1	1800/-
	कुल:-	145		

3. उक्त अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग-3 एवं वर्ग-4) के पदों पर प्रतिवर्ष कुल अनुमानित स्थापना व्यय 3,25,03,200/-(**तीन करोड़ पचीस लाख तीन हजार दो सौ**) **रूपये** मात्र भारित होगा। **(व्यय विवरणी संलग्न)**

4. पद धारकों को मूल वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे।

5. उक्त स्थापना व्यय की राशि का विकलन बजट शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय अन्तर्गत वेतन/भत्ते विषयशीर्ष से होगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा होंगे तथा स्थापना व्यय की निकासी जिला कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी।

6. उक्त पदो के सृजन के प्रस्ताव में दिनांक-10.03.2015 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-02 मे स्वीकृति प्राप्त है।

अनु0:- (क) व्यय विवरणी
(ख) जाँच पत्र
(ग) वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति संबंधी टिप्पणी पृष्ट की छायाप्रति।
(घ) मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संबंधी टिप्पणी पृष्ट की छायाप्रति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
19/3/15
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-जी0/स्था0(व्य0न्या0)-07-17/2014...914.../जे0, पटना, दिनांक...19-03-15...

प्रतिलिपि:- व्यय विवरणी के साथ जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु:-यथाकथित।

19/3/15
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-जी0/स्था0(व्य0न्या0)-07-17/2014...914.../जे0, पटना, दिनांक...19-03-15...

प्रतिलिपि:- व्यय विवरणी सहित महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा को निदेशित किया जाता है कि वर्त्तमान में कार्यरत न्यायालयों के अनुपात में ही न्यायालयों एवं सम्बद्ध कार्यालयों के लिए अराजपत्रित कर्म्मचारियों की नियुक्ति की जाय।

अनु:-यथाकथित।

19/3/15
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-जी0/स्था0(व्य0न्या0)-07-06/2014...914.../जे0, पटना, दिनांक...19-03-15...

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-10.03.2015 के मद संख्या-02 के प्रसंग में तथा प्रधान सचिव, समान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/15
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

न्यायमंडल शेखपुरा के अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड	ग्रेड पे	औसत वेतन	महंगाई भत्ता (90%)	आवास भत्ता (10%)	चिकित्सा भत्ता	धुलाई भत्ता	योग	प्रस्तावित पदों के प्रतिमाह कुल व्यय	प्रस्तावित पदों के प्रतिवर्ष कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	डी0जे0 सिरेस्तेदार	1	9300-34800	5400	21000	18900	2100	200	0	42200	42200 X 1 = 42200	42200 X 12 = 506400
2	क्रिमिनल सिरेस्तेदार	1	9300-34800	4200	18000	16200	1800	200	0	36200	36200 X 1 = 36200	36200 X 12 = 434400
3	सबजज सिरेस्तेदार	1	9300-34800	4200	18000	16200	1800	200	0	36200	36200 X 1 = 36200	36200 X 12 = 434400
4	मुंसिफ सिरेस्तेदार	1	9300-34800	4200	18000	16200	1800	200	0	36200	36200 X 1 = 36200	36200 X 12 = 434400
5	लिपिक	61	5200-20200	2400	9910	8919	991	200	0	20020	20020 X 61 = 1221220	1221220 X 12 = 14654640
6	स्टेनोग्राफर	20	5200-20200	2400	9910	8919	991	200	0	20020	20020 X 20 = 400400	400400 X 12 = 4804800
7	डिपोजिशन राईटर	10	5200-20200	2400	9910	8919	991	200	0	20020	20020 X 10 = 200200	200200 X 12 = 2402400
8	चालक	3	5200-20200	1900	9910	8919	991	200	0	20020	21920 X 3 = 65760	65760 X 12 = 789120
9	दफ्तरी	3	4440-7440	1800	7000	6300	700	200	60	14260	14260 X 3 = 42780	42780 X 12 = 513360
10	प्रोसेस सर्वर	5	4440-7440	1800	7000	6300	700	200	60	14260	14260 X 5 = 71300	71300 X 12 = 855600
11	नाईट गार्ड (चौकीदार)	2	4440-7440	1800	7000	6300	700	200	60	14260	14260 X 2 = 28520	28520 X 12 = 342240
12	पीउन/अर्दली	37	4440-7440	1800	7000	6300	700	200	60	14260	14260 X 37 = 527620	527620 X 12 = 6331440
	कुल :-	145									कुल:-	32503200

(तीन करोड़ पच्चीस लाख तीन हजार दो सौ रूपये)

17/2/15

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित ।

द्वारा: वित्त विभाग ।

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील सं0 1867/2006, मलिक मजहर सुल्तान एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.01.2019 को दिए गये न्यायादेश के आलोक में राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु वर्त्तमान में सृजित विभिन्न स्तरों के 1845 न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आवश्यक वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मियों की कुल संख्या में से पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त आवश्यक पदों का 50% (प्रथम चरण में) के अंतर्गत वर्ग 3 कोटि के 1645 एवं वर्ग 4 कोटि के 533 कुल 2178 (दो हजार एक सौ अठहत्तर) अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विषयांकित न्यायादेश में उल्लेखित उक्त निदेश का अनुपालन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के विभिन्न पदों की संशोधित रूप से प्रस्तावित आवश्यक संख्या का 50% पद प्रथम चरण में सृजन कराने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान में सृजित 1845 न्यायिक पदाधिकारियों एवं राज्य में स्थापित 38 जिला न्यायालय एवं 44 अनुमंडलीय न्यायालय की आवश्यकता के अनुसार बिहार सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्त्ती, प्रोन्नति, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2017 में वर्णित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 2178 निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया है। उक्त आवश्यक पदों का विवरण निम्नवत है:

क्र0सं0	पदनाम	सृजन हेतु आवश्यक पदों की संख्या	ग्रेडपे/ पुनरीक्षित लेवल
1	2	3	4
1.	लिपिक/समकक्ष पद (ग्रेड-III)	638	2400/4
2.	कोर्ट रीडर-सह-डिपोजिशन राईटर-सह-टाइपिस्ट (ग्रेड-III)	312	2400/4
3.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सह सिस्टम सहायक	312	1900/2
4.	प्रोसेस सर्वर	312	1900/2
5.	दफ्तरी	71	1800/1
6.	पिउन/ऑर्डली	533	1800/1
	कुल:	2178	

3. उक्त सृजित पदों पर नियुक्ति तब की जायेगी, जब इसके लिए पूर्व से सृजित न्यायिक पदाधिकारियों के पदों पर पदस्थापन हो जायेगा।

4. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल रूपया 66,47,32,224/-(छियासठ करोड़ सैतालीस लाख बत्तीस हजार दो सौ चौबीस) मात्र एवं संबंधित न्यायमंडल में देय अनुमान्य मकान भाड़ा भत्ता तथा देय अनुमान्य परिवहन भत्ता की राशि का अतिरिक्त वित्त भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। एतदसंबंधी वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी संलग्न है।

(क्0पृ0उ0)

सेवा में,

5. उक्त पदों के व्यय भार का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019 व्यय प्रशासन द्वारा मुख्यशीर्ष 00 लघुशीर्ष 105 सिविल और सेशन न्यायालय, मुख्यशीर्ष 0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अंतर्गत वेतन एवं अन्य विभागशीर्ष में स्वीकृत उपबंध से होगा।

6. उक्त पदों के विकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से होगी।

7. उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में दिनांक 27.08.2019 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं0 07 में स्वीकृति प्राप्त है।

8. राज्यादेश प्रारूप में वित्तीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु: (क) व्यय विवरणी।
(ख) जाँच पत्र।
(ग) वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति संबंधी टिप्पणी पृष्ठ की छायाप्रति।
(घ) मंत्रिपरिषद् स्वीकृति दिनांक 27.08.19 के मद सं0 07 संबंधी टिप्पणी की पृष्ठ की छायाप्रति।
(ड.) प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक दिनांक 28.06.19 की कार्यवाही की छायाप्रति।
(च) विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/ मदन किशोर कौशिक
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(उ0न्या0)-06-23/2010...../जे०, दिनांक .....

प्रतिलिपि:- व्यय विवरणी के साथ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/ मदन किशोर कौशिक
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(उ0न्या0)-06-23/2010.6569/जे०, दिनांक 11-09-19

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी सहित महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-'ए', विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/19

(मदन किशोर कौशिक)
सरकार के सचिव, बिहार।
11/9/19

अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अपुनरीक्षित ग्रेड पे	पुनरीक्षित वेतन का लेवल	औसत वेतन	महंगाई भत्ता (12%)	चिकित्सा भत्ता	योग	प्रस्तावित पदों के प्रतिमाह कुल व्यय	प्रस्तावित पदों के प्रतिवर्ष कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लिपिक/समकक्ष पद (ग्रेड-III)	638	2400	4	25500	3060	1000	29560	29560 X 638 = 18859280	18859280 X 12 = 226311360
2	कोर्ट रीडर-सह-डिपोजिशन राईटर-सह-टाईपिस्ट (ग्रेड III)	312	2400	4	25500	3060	1000	29560	29560 X 312 = 9222720	9222720 X 12 = 110672640
3	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर-सह-सिस्टम सहायक	312	1900	2	19900	2388	1000	23288	23288 X 312 = 7265856	7265856 X 12 = 87190272
4	प्रोसेस सर्वर	312	1900	2	19900	2388	1000	23288	23288 X 312 = 7265856	7265856 X 12 = 87190272
5	दफ्तरी	71	1800	1	18000	2160	1000	21160	21160 X 71 = 1502360	1502360 X 12 = 18028320
6	पिउन/ऑर्डली	533	1800	1	18000	2160	1000	21160	21160 X 533 = 11278280	11278280 X 12 = 135339360
	कुल :-	2178							कुल:-	664732224

(छियासठ करोड़ सैंतालीस लाख बत्तीस हजार दो सौ चौबीस रुपये) मात्र

टिप्पणी:-उपरोक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप देय मकान भाड़ा भत्ता एवं देय परिवहन भत्ता संबंधित न्यायमंडल में अनुज्ञेय दर के हिसाब से भुगतेय होगा जिसकी राशि उपरोक्त अनुमानित व्यय विवरणी में उल्लिखित प्रतिवर्ष व्यय राशि के अतिरिक्त होगी।

(मदन किशोर कौशिक)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(व्या0न्या0)-07-04/2022 ...../वि०, दिनांक .....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

अनौपचारिक रूप से प्रसारित ।

द्वारा:- *वित्त विभाग ।

विषय:- राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दायर वादों के त्वरित निष्पादन हेतु राज्य में गठित किए जाने वाले 54 अनन्य विशेष न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 432 पदों के सृजन के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दायर वादों के त्वरित निष्पादन हेतु राज्य में गठित किए जाने वाले 54 अनन्य विशेष न्यायालयों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 432 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	पदनाम	वास्तविक आवश्यकता	वेतन लेवल
1	वरीय कोर्ट सहायक-सह -बी.सी. (ग्रेड-1)	54 (प्रत्येक न्यायालय 1)	7
2	वरीय कार्यालय सहायक-सह -ओ.सी. (ग्रेड-1)	54 (प्रत्येक न्यायालय 1)	7
3	वरीय आशुलिपिक (ग्रेड-1)	54 (प्रत्येक न्यायालय 1)	7
4	कोर्ट रीडर-सह-डिपोजिशन राईटर-सह-टाईपिस्ट (ग्रेड-III)	54 (प्रत्येक न्यायालय 1)	4
5	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	54 (प्रत्येक न्यायालय 1)	2
6	चालक	54 (प्रत्येक न्यायालय 1)	2
7	पिउन/ऑर्डली	108 (प्रत्येक न्यायालय 2)	1
	कुल :-	432	

3. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल 22,23,41,760/-(बाईस करोड तेईस लाख एकतालीस हजार सात सौ साठ रूपये) मात्र प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। एतद्संबंधी वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी संलग्न है।

4. उक्त स्थापना के पदों के व्यय भार का विकलन बजटशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105-सिविल और सेसन्स न्यायालय-उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अंतर्गत वेतन/भत्ते विषय शीर्ष में स्वीकृत उपबंध से होगा, जिसका विपत्र कोड-27-2014001050001 होगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से होगी।

5. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मंत्रिपरिषद की दिनांक 29.11.2022 में मद संख्या-08 के रूप में उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(क्र0पृ0अ0)

4. [illegible] विधानीय अंतरीय वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु-(क) उक्त विवरणी।
(ख) यथोक्त।
(ग) बिल द्वारा इस प्रस्ताव संबंधी टिप्पणी पृष्ठ की छायाप्रति।
(घ) वित्तादेश, स्वीकृति दिनांक 29.11.2022 के मद सं0-08 संबंधी टिप्पणी की पृष्ठ की छायाप्रति।
(ङ.) प्रस्तावित अवर समिति की प्रस्ताव स्वीकृति संबंधी नियत विधानीय ज्ञापांक-4079/वि0 दिनांक 26.09.2022 की छायाप्रति।
(च) विधानीय अंतरीय वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(व्या0न्या0)-07-04/2022 ...../जे०, दिनांक .....

प्रतिलिपि:- व्यय विवरणी के साथ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-रूद्र प्रकाश मिश्र
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(व्या0न्या0)-07-04/2022 9909./जे०, दिनांक 06/12/22

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी सहित महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-'ए', विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12/22
(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन का लेवल	औसत वेतन	महंगाई भत्ता (34%)	मकान भाड़ा भत्ता (8%)	चिकित्सा भत्ता	योग	प्रस्तावित पदों के प्रतिमाह कुल व्यय	प्रस्तावित पदों के प्रतिवर्ष कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	विशेष कोर्ट सहायक-सह -बी. सी. (ग्रेड-1)	54	7	44900	15266	3592	1000	64758	64758 X 54 = 3496932	3496932 X 12 = 41963184
2	विशेष कार्यालय सहायक-सह -जे.सी. (ग्रेड-1)	54	7	44900	15266	3592	1000	64758	64758 X 54 = 3496932	3496932 X 12 = 41963184
3	विशेष आशुलिपिक (ग्रेड-1)	54	7	44900	15266	3592	1000	64758.	64758 X 54 =. 3496932	3496932 X 12 = 41963184
4	कोर्ट रीडर-सह-डिपोजिशन राईटर-सह-टाईपिस्ट (ग्रेड-III)	54	4	25500	8670	2040	1000	37210	37210 X 54 = 2009340	2009340 X 12 = 24112080
5	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	54	2	19900	6766	1592	1000	29258	29258 X 54 = 1579932	1579932 X 12 = 18959184
6	खलक	54	2	19900	6766	1592	1000	29258	29258 X 54 = 1579932	1579932 X 12 = 18959184
7	पिऊन/ऑर्डली	108	1	18000	6120	1440	1000	26560	26560 X 108 = 2868480	2868480 X 12 = 34421760
	कुल :-	432							कुल:-	22,23,41,760

(बाईस करोड़ तेईस लाख एकतालीस हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र।

(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

R.C No:- 707
14.11.22

वित्त विभाग

पत्रांक सं0-वी0/स्था0(स्था0प्रा0)-07-02/2022-2266/वि0, दिनांक ...11.11.22

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
लोकनायक जयप्रकाश पथ, पटना ।

प्रकाशित पत्र की प्रतिलिपि ।

द्वारा:- वित्त विभाग ।

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0-Cr. Appeal No.-1101/2019 में दिनांक 11.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के सभी 37 न्यायमंडलों में Vulnerable Witness Deposition Centre के स्थापना हेतु आवश्यक 37 Office-In-charge एवं 37 Technical Assistant- cum-Coordinator सहित कुल 74 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0-Cr. Appeal No.-1101/2019 में दिनांक 11.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के सभी 37 न्यायमंडलों में Vulnerable Witness Deposition Centre के स्थापना हेतु 74 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त 74 पदों में प्रत्येक न्यायालय के लिए एक Office-In-charge एवं एक Technical Assistant- cum-Coordinator की सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. उक्त पदों में से Office-In-charge के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हत्ता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं कम्प्यूटर में निपुणता तथा Technical Assistant- cum-Coordinator के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हत्ता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं आई0टी0/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स ('O' Level सर्टिफिकेट कोर्स वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता) होगी।

4. उक्त दोनों पदों का वेतनमान लेवल-4 (GP-2400) होगा। उक्त पदों के दायित्व Guidelines for recording of evidence of Vulnerable Witnesses के Section-42 के अनुरूप होगी (छायाप्रति संलग्न है)।

5. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल रु0 6,86,09,544/-(छः करोड छियासी लाख नौ हजार पाँच सौ चौवालीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर पडेगा। एतद्संबंधी वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी संलग्न है।

6. उक्त वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी औसत वेतनमान के आधार पर तैयार की गयी है। वस्तुतः उक्त पदों पर नियुक्त होनेवाले कर्मियों का वेतन, महानिबंधक, उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक 25975 दिनांक 30.04.2022 के अनुसार अनुमान्य वेतन लेवल के प्रारंभिक क्रम के अनुसार देय होगा। साथ ही अनुमान्य भत्तों का भुगतान राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

7. उक्त पदों के वेतन एवं अन्य भत्तों में व्यवहार का विकलन-बजट मुख्यशीर्ष-2014- न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 105 सिविल और सेशन्स न्यायालय, उपशीर्ष 0001-सिविल एवं सत्र न्यायालय, समेकित वित्त कोड-27-2014001050001 के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते विषयशीर्ष में स्वीकृत प्रबंध से होगा।

8. [illegible]

प्रस्तावित के परिप्रेक्ष्य में मंत्रिपरिषद की दिनांक 08.11.2022 के मद संख्या-38 के क्रम में व्यय राशि के मुद्रण को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. राज्यादेश स्वरूप वित्तीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

अनु: (क) व्यय विवरणी।
(ख) जीप पत्र।
(ग) वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति संबंधी टिप्पणी पृष्ठ की छायाप्रति।
(घ) मंत्रिपरिषद् स्वीकृति दिनांक 08.11.2022 के मद सं0-38 संबंधी टिप्पणी की पृष्ठ की छायाप्रति।
(ङ.) प्रशासी पदवर्ग समिति की प्राप्त स्वीकृति संबंधी वित्त विभागीय ज्ञापांक-9079/वि0 दिनांक 26.09.2022 की छायाप्रति।
(च) विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(व्य0न्या0)-07-02/2022-9160-/जे०, दिनांक ...11.11.22

प्रतिलिपि:- व्यय विवरणी के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(व्य0न्या0)-07-02/2022-9160-/जे०, दिनांक ..11.11.22

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी सहित महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-'ए', विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0 बी0/स्था0(व्य0न्या0)-07-02/2022-9160-/जे०, दिनांक ..11.11.22

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 08.11.2022 के मद सं0-38 के प्रसंग में तथा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0 बी0/स्था0(व्य0न्या0)-07-02/2022-9160-/जे०, दिनांक ..11.11.22

प्रति, उपसचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय ज्ञापांक पर अवलोकनार्थ।

Seen, keep it in Concern file.

D.J. SK
17.11.22

अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन	वेतनमान	ग्रेड वेतनमान	महंगाई भत्ता (34%)	आवास भत्ता (8%)	चिकित्सा भत्ता	परिवहन भत्ता	परिवहन भत्ता पर महंगाई भत्ता @8%	योग	प्रस्तावित पदों के प्रतिमाह कुल व्यय	प्रस्तावित पदों के कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	[redacted]	37	4	25500-81000	53250	18105	4260	1000	600	48	77263	77263 X 37 = 2858731	2858731 X [illegible]
2	[redacted]	37	4	25500-81000	53250	18105	4260	1000	600	48	77263	77263 X 37 = 2858731	2858731 X
कुल :- 74												कुल :-	

(दो करोड़ तिरासी लाख बौ हजार सौंन सौ [illegible])

(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या वी0/स्था0(व0न्या0)-06-23/2010...../वि०, दिनांक .....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

अतिरिक्त प्रभार में

द्वारा:- वित्त विभाग ।

विषय:- बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के अनुसार राज्य के व्यवहार न्यायालयों हेतु तकनीकी कार्यबल के अंतर्गत आवश्यक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर-सह-सिस्टम सहायक के 1,643 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

.....

आदेश:- स्वीकृत।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान में न्यायिक पदाधिकारियों (अनुमंडलीय न्यायालय हेतु सृजित न्यायिक पदाधिकारी के पद को छोड़कर) के सृजित 1600 पद, राज्य में स्थापित 37 जिला न्यायालय एवं 43 अनुमंडलीय न्यायालय के आधार पर बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में तकनीकी कार्यबल के अंतर्गत आवश्यक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर-सह-सिस्टम सहायक के 1,643 पदों के पदों के सृजन किया गया है।

3. बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के स्टाफिंग पैर्टन के अनुसार जिला न्यायालय स्थापना के अंतर्गत संगणक कोषांग में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर-सह-सिस्टम सहायक के पद का तथा शेष कार्यालयों के लिए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद का प्रावधान है। सृजित कुल 1,643 पदों में उक्त दोनों पद सम्मिलित रूप से उल्लेखित है।

4. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल रूपया **56,11,56,792/- (छप्पन करोड ग्यारह लाख छप्पन हजार सात सौ बेरानवे रूपये)** मात्र एवं संबंधित न्यायमंडल में देय अनुमान्य मकान भाड़ा भत्ता तथा देय अनुमान्य परिवहन भत्ता की राशि का अतिरिक्त वित्त भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। एतद्संबंधी वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी संलग्न है।

5. उक्त पदों के व्यय भार का विकलन बजट मुख्यशीर्ष-2014 --न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय, उपशीर्ष-0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अंतर्गत वेतन एवं भत्ते विषयशीर्ष में स्वीकृत उपबंध से होगा।

6. उक्त पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से होगी।

क्र0पृ030

[redacted]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0 बी0/स्था0(उ0न्या0) 06 23/2010...../जे०, दिनांक .....

प्रतिलिपि: व्यय विवरणी के साथ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-रमेश चन्द मालवीय
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(उ0न्या0)-06-23/2010...../जे०, दिनांक .....

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी सहित महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 'ए', विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित.

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(उ0न्या0)-06-23/2010...../जे०, दिनांक .....

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.03.2023 के मद सं0-04 के प्रसंग में तथा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-रमेश चन्द मालवीय
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-बी0/स्था0(उ0न्या0)-06-23/2010..2558../जे०, दिनांक 31.03.23

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31.3.23

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार।

[redacted]

अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन का स्केल	औसत वेतन	महंगाई भत्ता (38%)	चिकित्सा भत्ता	योग	प्रस्तावित पदों के प्रतिमाह कुल व्यय	प्रस्तावित पदों के प्रतिवर्ष कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Data Entry Operator/Data Base Operator-cum-System Assistant	1643	2	19900	7562	1000	28462	28462 X 1643 46763066	46763066 X 12 = 561156792
	कुल	1643						कुल:-	56,11,56,792

(छप्पन करोड़ ग्यारह लाख छप्पन हजार सातसौबेरानवे रुपये) मात्र।

2. अनुबंध पर के इकरार के फलस्वरूप देय मकान भाड़ा भत्ता एवं देय परिवहन भत्ता संबंधित मानकोंटन में अनुमान्य दर के हिसाब से भुगतेय होगा जिसकी राशि उपरोक्त अनुमानित व्यय विवरणी में उल्लेखित प्रतिवर्ष व्यय राशि के अतिरिक्त होगी।

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार।

seen, keep it with concern
guard file for fotuse reference.

D. S. SKP
03.04.2023

पत्र सं0-सी0/एल0एस0-10/2017...../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग



प्रेषक,

पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा मे,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:- वित्त विभाग।

पटना, दिनांक.....

विषय:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वेब पोर्टल के संचालन हेतु बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना, उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति एवं सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 39 (उनचालीस) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के स्थायी पदसृजन के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत

उपर्युक्त विषयक के संबंध मे निदेशानुसार कहना है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में एन0आई0सी0 के माध्यम से सभी लोगों को ऑन लाईन विधिक सहायता/आवेदन/शिकायत/अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु लिगल सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम के अन्तर्गत एक वेब पोर्टल विकसीत किया गया है, उक्त वेब पोर्टल पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना, उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति, पटना एवं सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा डाटा को अपलोड किया जाना सुनिश्चत किया गया है, जिसके कारण बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना एवं सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के स्थायी पदसृजन की स्वीकृति निम्न रूपेण प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	संस्थान	पदों की सं0	वेतन स्तर	अभियुक्ति
1.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	01 (एक)	लेवल-02	---
2.	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना	01 (एक)	लेवल-02	---
3.	जिला विधिक सेवा प्राधिकार	37 (सैतीस)	लेवल-02	प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए एक पद
	कुल पद:-	39 (उन्चालीस)		

2. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रू0-1,25,01,516/-(एक करोड़ पच्चीस लाख एक हजार पाँच सौ सोलह) रूपये मात्र होगा। उक्त व्यय मुख्य शीर्ष-2014, विपत्र कोड-27-2014001140002 के अन्तर्गत होगा। (अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी संलग्न है)।

3. राशि की निकासी बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना के लिए सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी

4. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, सचिव, उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार होंगे।

5. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-31.03.2021 के मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृत।

5. इस स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

अनु0: (क) व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

P.C. Gandhi
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....2363...../जे0, पटना, दिनांक.....05/04/2021.....

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

P.C. Gandhi
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....2363...../जे0, पटना, दिनांक.....05/04/2021.....

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार/सचिव, उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति एवं सचिव, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

P.C. Gandhi
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....2363...../जे0, पटना, दिनांक.....08/04/2021.....

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-31.03.2021 के मद सं0-04 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

Seer, send its Copy to Full Time Secretary, D.L.S.A, Sheikhpura and Copy of the same posted in Concerned Limit future

P.C. Gandhi
सरकार के सचिव, बिहार।
8.4.2021

बिहार सरकार

विधि विभाग

पत्र संख्या-बी/स्था0(व्य0न्या0)-07-14/2019/...../जे0, पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:- *वित्त विभाग।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:- न्यायमंडल पश्चिम चम्पारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बाँका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथासंशोधित) के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 (एक सौ इकहत्तर) विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथासंशोधित) के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु न्यायमंडल पश्चिम चम्पारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बाँका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 (एक सौ इकहत्तर) विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	पदनाम	नव सृजित पदों की संख्या	वेतन स्तर
1	वरीय न्यायालय सहायक-सह-बी.सी. (ग्रेड-I)	19 (प्रत्येक न्यायालय 1)	7
2	वरीय कार्यालय सहायक-सह-ओ.सी. (ग्रेड-I)	19 (प्रत्येक न्यायालय 1)	7
3	वरीय आशुलिपिक (ग्रेड-I)	19 (प्रत्येक न्यायालय 1)	7
4	कोर्ट रीडर-सह-डिपोजिशन राईटर (ग्रेड-III)	19 (प्रत्येक न्यायालय 1)	4
5	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	19 (प्रत्येक न्यायालय 1)	2

6	चालक	19 (प्रत्येक न्यायालय 1)	2
7	प्रोसेस सर्वर	19 (प्रत्येक न्यायालय 1)	2
8	परिचारी(चपरासी/आदेशपाल)	38 (प्रत्येक न्यायालय 2)	1
	कुल :-	171	

3. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल 10,12,38,840/-(दस करोड़ बारह लाख अड़तीस हजार आठ सौ चालीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। एतद्संबंधी वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी संलग्न है।

4. उक्त स्थापना के पदों के व्यय भार का विकलन बजट मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अंतर्गत वेतन भत्ते विषय शीर्ष में स्वीकृत उपबंध से होगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित न्यायमंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित न्यायमंडल के जिला कोषागार से होगी।

5. उक्त सृजित किये जाने वाले पदों को पीठासीन पदाधिकारी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकतानुसार भरा जायेगा।

6. उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में दिनांक-05.08.2026 की मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं0-09 में स्वीकृति प्राप्त है।

7. राज्यादेश प्रारूप पर वित्तीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक:-(क) व्यय विवरणी।

(ख) जाँच पत्र।

(ग) प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक दिनांक-16.07.2026 की कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति।

(घ) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-05.08.2026 में दी गयी स्वीकृति से संबंधित पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-बलराम दूबे

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक. .....

प्रतिलिपि:- व्यय विवरणी की प्रति के साथ सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

ह0/-बलराम दूबे

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः- व्यय विवरणी की प्रति के साथ महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-3) तथा प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-11), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः-यथोक्त।

ह0/-बलराम दूबे
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-05.08.2026 के मद सं0-09 के प्रसंग में तथा अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-बलराम दूबे
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....6422...../जे0, पटना, दिनांक..07.8.26

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

07-08-26
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।
07.08.26

अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन का लेवल	औसत वेतन	महंगाई भत्ता (60%)	मकान भाड़ा भत्ता (10%)	चिकित्सा भत्ता	योग	प्रस्तावित पदों का प्रतिमाह कुल व्यय	प्रस्तावित पदों का प्रतिवर्ष कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वरीय न्यायालय सहायक-सह -बी.सी. (ग्रेड-1)	19	7	44900	26940	4490	1000	77330	77330 X 19 = 1469270	1469270 X 12 = 17631240
2	वरीय कार्यालय सहायक-सह -ओ.सी. (ग्रेड-1)	19	7	44900	26940	4490	1000	77330	77330 X 19 = 1469270	1469270 X 12 = 17631240
3	वरीय आशुलिपिक (ग्रेड-1)	19	7	44900	26940	4490	1000	77330	77330 X 19 = 1469270	1469270 X 12 = 17631240
4	कोर्ट रीडर-सह-डिपोजिशन राईटर (ग्रेड-III)	19	4	25500	15300	2550	1000	44350	44350 X 19 = 842650	842650 X 12 = 10111800
5	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	19	2	19900	11940	1990	1000	34830	34830 X 19 = 661770	661770 X 12 = 7941240
6	चालक	19	2	19900	11940	1990	1000	34830	34830 X 19 = 661770	661770 X 12 = 7941240
7	प्रोसेस सर्वर	19	2	19900	11940	1990	1000	34830	34830 X 19 = 661770	661770 X 12 = 7941240
8	परिचारी(चपरासी/आदेशपाल)	38	1	18000	10800	1800	1000	31600	31600 X 38 = 1200800	1200800 X 12 = 14409600
	कुल :-	171							कुल:-	10,12,38,840

(दस करोड़ बारह लाख अड़तीस हजार आठ सौ चालीस रूपये) मात्र।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

पत्र संख्या-02/स्था0(व्य0न्या0)-07-33/2026/..7311.../जे0, पटना, दिनांक..07.9.26

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:- *वित्त विभाग।

विषय:- **व्यवहार न्यायालयों के कर्मचारियों को प्रोन्नति दिये जाने के निमित्त उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड-III) (वेतन स्तर-4) के स्वीकृत 7527 पदों में से 1478 पदों को उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड-II) (वेतन स्तर-6) एवं 1098 पदों को उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-I) (वेतन स्तर-7) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पदों को उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड-III) (वेतन स्तर-4) का 4951 पद, उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड-II) (वेतन स्तर-6) का 1478 पद एवं उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-I) (वेतन स्तर-7) का 1098 पद के रूप में पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश:- **स्वीकृत।**

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार ने व्यवहार न्यायालयों के कर्मचारियों को प्रोन्नति दिये जाने के निमित्त उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड-III) (वेतन स्तर-4) के स्वीकृत 7527 पदों में से 1478 पदों को उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड-II) (वेतन स्तर-6) एवं 1098 पदों को उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-I) (वेतन स्तर-7) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पदों को उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड-III) (वेतन स्तर-4) का 4951 पद, उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड-II) (वेतन स्तर-6) का 1478 पद एवं उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-I) (वेतन स्तर-7) का 1098 पद के रूप में पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. महानिबंधक(प्रभारी), माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक- 62594, दिनांक- 13.07.2026 के द्वारा बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्त्ती, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा-शर्त्ते) नियमावली, 2022 की अनुसूचियों में उल्लेखित उच्चवर्गीय लिपिक ग्रेड-I, उच्चवर्गीय लिपिक ग्रेड-II एवं उच्चवर्गीय लिपिक ग्रेड-III के अंतर्गत पदों का नाम सूचीबद्ध किया गया है, जो निम्नवत् है:-

उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-I)	उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-II)	उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-III)
वरीय न्यायालय सहायक-सह-लिपिक	सत्र सहायक	उच्चवर्गीय लिपिक (लिपिक)
वरीय कार्यालय सहायक-सह-लिपिक	वाद सहायक	डिस्पैचर

उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-I)	उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-II)	उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-III)
वरीय न्यायालय सहायक-सह-बी0सी0	प्रकीर्ण सहायक	कनीय कार्यालय सहायक-सह-ओ0सी0
वरीय कार्यालय सहायक-सह-ओ0सी0	ब्यान सहायक	प्रकीर्ण लिपिक
वरीय न्यायालय सहायक(प्रभारी जी0आर0)	न्यायालय सहायक-सह-बी0सी0	कनीय न्यायालय सहायक-सह-बी0सी0
वरीय न्यायालय सहायक-सह-परिवाद लिपिक	कार्यालय सहायक-सह-ओ0सी0	प्रधान लिपिक(नकलकर्त्ता)
प्रोटोकॉल अधिकारी	प्रधान लिपिक(नायब नाजीर)	सहायक अभिलेख संधारक
प्रधान नकलखाना लिपिक	कार्यालय सहायक	
प्रधान अभिलेख संधारक	प्रभारी लिपिक	
	प्रधान लिपिक (नकलखाना लिपिक)	
	न्यायालय सहायक-सह-वाद लिपिक	
	प्रकीर्ण लिपिक	
	वाद लिपिक	

4. उक्त पदों के उत्क्रमण के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल 73,30,41,360/-(तिहत्तर करोड़ तीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। एतद्संबंधी वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी संलग्न है।

5. उक्त स्थापना के पदों के व्यय भार का विकलन बजट मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय, उपशीर्ष- 0001- सिविल और सत्र न्यायालय के अंतर्गत वेतन भत्ते विषय शीर्ष में स्वीकृत उपबंध से होगा।

6. उक्त पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित न्यायमंडलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित न्यायमंडल के जिला कोषागार से होगी।

7. उक्त पदों के उत्क्रमण एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव में दिनांक-02.09.2026 की मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं0-23 में स्वीकृति प्राप्त है।

8. राज्यादेश प्रारूप पर वित्तीय आंतरिक सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक:-(क) व्यय विवरणी।

(ख) जाँच पत्र।

(ग) प्रशासी पदवर्ग समिति की कार्यवाही ज्ञापांक-7859/वि0, दिनांक-21.08.2026 की सत्यापित छायाप्रति।

(घ) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-02.09.2026 में दी गयी स्वीकृति से संबंधित पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

07.09.26

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....7311...../जे0, पटना, दिनांक...07.9.26

प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, को व्यय विवरणी की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....7311...../जे0, पटना, दिनांक...07.9.26

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-11), विधि विभाग, बिहार, पटना को व्यय विवरणी की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....7311...../जे0, पटना, दिनांक...07.9.26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-02.09.2026 के मद सं0-23 के प्रसंग में तथा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....7311...../जे0, पटना, दिनांक...07.9.26

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

07.09.26
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन स्तर	वेतन स्तर में न्यूनतम वेतन	महंगाई भत्ता (60%)	मकान भाड़ा भत्ता (10%)	चिकित्सा भत्ता	कुल	पदों की संख्या	प्रतिमाह कुल व्यय	प्रतिवर्ष कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उच्च वर्गीय लिपिक, ग्रेड-II	लेवल-6	35400	21240	3540	1000	61180	1478	90424040	1085088480
2	उच्च वर्गीय लिपिक, ग्रेड-I	लेवल-7	44900	26940	4490	1000	77330	1098	84908340	1018900080
	A							**2576**		**2103988560**
1	उच्च वर्गीय लिपिक, ग्रेड-III	लेवल-4	25500	15300	2550	1000	44350	7527	333822450	4005869400
2	B	लेवल-4	25500	15300	2550	1000	44350	**2576**	114245600	**1370947200**

अतएव कुल अनुमानित वार्षिक व्यय = A-B = 2,10,39,88,560 – 1,37,09,47,200 = 73,30,41,360/-

(तिहत्तर करोड़ तीस लाख एकतालीस हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र है।

07-09-16

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार